यद्यपि 1757 से पहले भी E.I.C भारतीय व्यापार के द्वारा लाभार्जन कर रही थी, परन्तु इस लाभार्जन के बाद भी व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष मे था। ऐसा इसलिये, क्योंकि जजमानी व्यवस्था के कारण जहाँ INDIAN Economy पुरी तरह आत्मनिर्भर रही थी वहीं भारतीय शिल्प एवं नगदी फसलो का E.I.C. बड़े पैमाने पर इंग्लैण्ड एवं विश्व बाजार मे निर्यात कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि सोने-चाँदी के आवक की दिशा हर हाल मे इंग्लैण्ड से भारत की तरफ थी अगर इस समय अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की लक्ष्यो का अध्ययन किया जाये, तो उनका एक सबसे बड़ा लक्ष्य इंग्लैण्ड मे वाणिज्यिक पूँजी का निर्माण था न कि इंग्लैण्ड से सोने-चाँदी का बहिर्गमन। स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन की दिशा बदली जानी थी तो E.I.C के सामान के खरीद के स्थानीय स्रोत साधन निर्मित किये जाने थे। यह तबतक नही हो सकता था जबतक E.I.C. एक व्यापारिक कंपनी से राजनैतिक सत्ता के रूप में

संक्रमित नहीं होती। स्पष्ट है प्लासी व बक्सर की लड़ाई E.I.C. पर ऐतिहासिक दुर्घटनाओं के द्वारा थोपा नहीं गया थी बल्कि औपनिवेशिक रणनीति के सोची समझी साजीश का परिणाम था। इस तरह व्यापारिक एकाधिपत्य के द्वारा भारतीय अर्थ० के शोषण के लिये यह आवश्यक था कि भारतीय राजस्व पर E.I.C अपना अधिकार स्थापित करती। E.I.C ने दीवानी अधिकार की प्राप्ति के बाद इस दिशा मे कदम उठाया। क्रमशः राजस्व की अलग-2 औपनिवेशिक बन्दोबस्तो को रेखांकित किया गया। इन अलग-अलग राजस्व बन्दोबस्तो से प्राप्त होनेवाली आय को भारत मे ब्रिटिश निवेश (English Investment) का नाम दिया गया और इसी निवेश के आधार पर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हुआ। उपनिवेशी अधिरचनाओ को इन्हीं संसाधनो के दोहन के लिये क्रमशः विकसित किया गया। इसी निवेश के द्वारा E.I.C. ने भारतीय शिल्प एवं नगदी फसलो की खरीदारी की. जिसे विश्व बाजार मे बेचकर लाभ E.I.C के शेयरधारको को हस्तानांतरित कर दिया गया। चूंकि धन का हस्तानांतरण एकतरफा (Unilateral) था. इसलिये इसे धन के निर्गमन की संज्ञा दी गयी